क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए?

अरविंद केजरीवाल जानना चाहते हैं आपकी राय

मेरे प्रिय दिल्लीवासी,

दिल्ली विधानसभा चुनाव में 'आम आदमी पार्टी' को और झाड़ू को 28 सीटें मिलीं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। यह आम आदमी की जीत है, सच्चाई और ईमानदारी की जीत है।

लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए। आठ सीट कम रह गईं। दिल्ली में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आम आदमी की स्वच्छ राजनीति से डर कर ही पूर्व में गोवा-हिमाचल-छत्तीसगढ़-यूपी में जोड़-तोड़ कर सरकार बनाती रही भाजपा, सबसे बड़े दल होने के बाद भी सरकार बनाने की अपनी ज़िम्मेदारी से भाग गई।

इस दौरान कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि हम 'आम आदमी पार्टी' को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। उधर बीजेपी वालों ने कहना शुरू किया कि हम दिल्ली की जनता के हित में चाहते हैं कि 'आम आदमी पार्टी' सरकार बनाए और हम उन्हें मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

हमने तो इन दोनों पार्टियों से समर्थन मांगा ही नहीं था। खुद ही समर्थन देने की बात कहने लगे और फ्री में समर्थन देने लगे। हमने तो सुना था कि एक-एक एम.एल.ए. को खरीदने के दस-दस करोड़ रुपये लगते हैं।

पहले हमें यह सोचना चाहिए कि 'आम आदमी पार्टी' क्यों बनी? 'आम आदमी पार्टी' का जन्म ही बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भ्रष्ट, आपराधिक और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हुआ था। आम आदमी पार्टी सत्ता भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है। जब इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी कराह उठा तो इस देश के आम लोगों ने मिलकर 'आम आदमी पार्टी' बना ली। ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार कैसे बना सकते हैं?

लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 'आम आदमी पार्टी' अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 'आम आदमी पार्टी' को इन पार्टियों से बाहर से मिल रहे समर्थन पर क्या हर्ज है? जितने दिन ये पार्टियां सरकार चलाने देती हैं, सरकार चलाओ। जिस दिन ये पार्टियां सरकार गिरा दें तो जनता के बीच जाकर चुनाव दुबारा लड़ लो। तब जनता इन पार्टियों को सबक सिखलाएगी।

आज बाकी सभी पार्टियां जैसे-तैसे जोड़-तोड़ करके सत्ता हासिल करने में लगी हुई हैं। लेकिन हम राजनीति में सत्ता हासिल करने नहीं आए। हम आम जनता हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हैं। दिल्ली की आम जनता के कुछ मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत दुखी है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी भी पड़े तो जनता के मुद्दों पर सभी पार्टियों में आम सहमति बनाकर सरकार बनाई जाए। इसीलिए हमने दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिखी। इन दोनों पार्टियों को ऐसे 18 मुद्दें भेजें जिनसे दिल्ली की जनता बुरी तरह त्रस्त है। हमने इन दोनों पार्टियों से पूछा कि यदि 'आम आदमी पार्टी' सरकार बनाती है तो क्या बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दों पर सहयोग करेंगे? ये 18 मुद्दें निम्नलिखित हैं :-

मुद्दा नं.-1: दिल्ली सरकार का कोई भी विधायक, मंत्री या अफ़सर लालबत्ती की गाड़ी नहीं लेगा, बड़े बंगले में नहीं रहेगा और अपने लिए विशेष सिक्योरिटी नहीं लेगा। हर नेता और अफ़सर आम आदमी की तरह रहेगा।

मुद्दा नं.-2: भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख़्त जनलोकपाल बिल पास किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोटालों की जांच की जाएगी।

मुद्दा नं.-3: दिल्ली में स्वराज कानून स्थापित किया जाएगा। अपने-अपने मोहल्ले, कालोनी और गलियों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार सीधे जनता को दिए जाएंगे। दिल्ली में विधायक और पार्षद फंड बंद किया जाएगा। यह पैसा सीधे मोहल्ला सभाओं को दिया जाएगा ताकि जनता तय करे कि सरकारी पैसा उनके इलाके में कहां और कैसे खर्च हो।

मुद्दा नं.-4: दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी।

मुद्दा नं.-5: बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाएगा। दिल्ली में बिजली के बिल आधे किए जाएंगे।

मुद्दा नं.-6: दिल्ली में तेज चल रहे बिजली के मीटरों की जांच करायी जाएगी।

मुद्दा नं.-7: दिल्ली के हर घर को 700 लीटर साफ़ पानी प्रतिदिन मुफ़्त दिया जाएगा।

मुद्दा नं.-8: दिल्ली की सभी अनाधिकृत कालोनियों को एक वर्ष के अंदर नियमित करके इनमें तुरंत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुद्दा नं.-9: झुग्गीवासियों को जब तक पक्के मकान नहीं दिए जाते उनकी झुग्गियों को तोड़ा नहीं जाएगा।

मुद्दा नं.-10: स्थायी और नियमित कार्यों में ठेकेदारी पर कर्मवारियों को रखने की प्रथा बंद करके सभी लोगों को नियमित किया जाएगा।

मुद्दा नं.-11: वैट का सरलीकरण किया जाएगा। वैट की दरों की पुनर्समीक्षा की जाएगी

मुदद्दा नं.-12: दिल्ली में किराना में FDI नहीं आने दिया जाएगा।

मुद्दा नं.-13: किसानों को वो सभी सुविधाएं और सब्सिडी दी जाएगी जो दूसरे राज्यों के किसानों को उपलब्ध हैं। ग्रामसभा की मंजूरी के बिना किसी भी गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। दिल्ली में लालडोरा का विस्तार किया जाएगा।

मुद्दा नं.-14: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर किया जाएगा। दिल्ली में 500 से भी अधिक नये सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन का सिस्टम बंद किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।

मुद्दा नं.-15: दिल्ली में नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे और सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर इलाज का प्रबंध किया जाएगा।

मुद्दा नं.-16: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल सुरक्षा दल बनाया जाएगा। दिल्ली में इतनी नई अदालतें बनाई जाएगी और जज नियुक्त किए जाएंगे ताकि महिलाओं के साथ उत्पीड़न के किसी भी मामले में तीन से छः महीने के अंदर सज़ा हो और सख़्त से सख़्त सज़ा हो।

मुद्दा नं.-17: दिल्ली में इतनी नई अदालतें खोली जाएंगी और इतने नए जजों की नियुक्ति की जाएगी ताकि कोई भी मामला छः महीने से एक साल के अंदर निपटाया जा सके।

मुद्दा नं.-18: अन्य पार्टियां केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का साथ देगी।

देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की।

हमारे इस पत्र का बीजेपी वालों ने जवाब देने से मना कर दिया। जबकि बीजेपी पहले कह रही थी कि हम दिल्ली वालों के हित में 'आम आदमी पार्टी' को मुद्दों पर समर्थन देंगे। इससे साफ़ जाहिर हो गया कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति खेल रही थी- ना उनके मन में दिल्ली वालों का हित है और ना मुद्दों पर समर्थन देने की इच्छा।

कांग्रेस का जवाब आया है। उनका कहना है कि सरकार बनाने के बाद इनमें से 16 मुद्दों पर आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही उन मुद्दों पर निर्णय ले सकेंगे। बाकि दो मुद्दों पर हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी ये हमारी सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाए? सबको याद है कि पहले भी इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह जी और श्री चंद्रशेखर की सरकार राजनैतिक चाल चल कर गिरा दी थी।

लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अभी कोई बदमाशी नहीं करेगी। अभी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है। कम से कम छः महीने तक तो कांग्रेस कोई बदमाशी नहीं करेगी। ऐसे में 'आम आदमी पार्टी' को दिल्ली में छः महीने की सरकार बना लेनी चाहिए और दिल्ली के हित के मुद्दों को लागू करना चाहिए।

हमारे सामने एक बड़ा धर्म संकट है। कई साथियों का मानना है कि हमें कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से किसी पार्टी का समर्थन लेना ही नहीं चाहिए और सीधे दिल्ली में दुबारा चुनाव होने चाहिए। कुछ अन्य साथियों का कहना है कि हमें दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए।

हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में बैठ कर फैसला नहीं लेंगे। हम यह प्रश्न जनता से सामने रख रहे हैं क्योंकि 'आम आदमी पार्टी' कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। इस प्रक्रिया में आप सब की राय ही सर्वोच्च होगी। आप अपनी राय निम्नलिखित तरीके से भेज सकते हैं-

- **आप अपनी राय हमें SMS से भेज सकते हैं। यदि आपका जवाब 'हां' है तो 'Yes' और 'नहीं' है तो 'No' लिखकर 08806110335 पर भेज दें**
- **आप अपनी राय हमें 08806110335 पर कॉल करके या www.aamaadmiparty.org और www.facebook.com/AamAadmiParty पर जाकर भी दे सकते हैं**